



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012020-215618  
CG-DL-E-21012020-215618

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]  
No. 262]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2020/पौष 30, 1941  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2020/PAUSHA 30, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 273(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

दिसंबर 31, 2019

श्री संजीव कुमार राजपूत (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “याची” कहा गया है), ने अधोहस्ताक्षरी को एक याचिका तारीख 13 अगस्त, 2018 भेजी है जिसके द्वारा उसने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “न.दि.न.पा.प.” कहा गया है) की उसकी सदस्यता के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991” कहा गया है) की धारा 15(1)(क) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन श्री सुरेंद्र सिंह (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “प्रत्यर्थी” कहा गया है) की निर्हरता की मांग की है।

और, याची, ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थी दिल्ली विधानसभा, 2015 के लिए साधारण निर्वाचन में 10 फरवरी, 2015 को दिल्ली छावनी सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 38 से दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में

निर्वाचित हुआ था। तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी को, अगस्त, 2015 में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (दि.रा.रा.रा.) के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा फ्लैट सं. 12, टाइप-V, यशवंत प्लेस बाजार, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का किराया मुक्त आवास आबंटित किया गया था जो उसी समय से उसके अधिभोग में रहा है। प्रत्यर्थी, जो दिल्ली छावनी से दिल्ली विधान सभा का सदस्य है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 05.09.2014 द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार नई दिल्ली, नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था।

और, याची ने यह अभिकथन किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने प्रत्यर्थी को 18000/- रुपए प्रति मास के किराए पर एक सुसज्जित फ्लैट अर्थात् फ्लैट सं. 13, टाइप-V, यशवंत प्लेस बाजार, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने प्रत्यर्थी को अपने पालिका केंद्र भवन, नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में सज्जित कार्यालय भी निःशुल्क आबंटित किया है। याची के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा आबंटित ऊपर उल्लिखित दोनों संपत्तियों में से प्रत्येक की किराये की बाजार मासिक दर लगभग 1,00,000/- रुपए है।

और, याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी इस आधार पर लाभ का पद धारण कर रहा है कि वह ऊपर उल्लिखित संपत्तियों के कब्जे और अधिभोग द्वारा ऐसे फायदे प्राप्त कर रहा है जो, सदस्य, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पद को धारण करने से प्रोद्भूत होने वाला फायदा है और इसलिए, वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के अधीन लाभ का पद धारण करने के संबंध में निर्हित किए जाने का पात्र है।

और, उक्त याचिका भारत निर्वाचन आयोग को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) की अपेक्षानुसार उसकी राय इस पत्र पर मांगने के लिए निर्दिष्ट की गई थी कि क्या प्रत्यर्थी उक्त अधिनियम की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निर्हता से ग्रस्त हो गया है।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने, याचिका की समीक्षा करने के पश्चात्, यह राय दी है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 4 के मात्र पठन से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में ऐसे दो विधान सभा सदस्यों, जिन्हें किसी ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया है जो पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आता है, को नियुक्त करना कानूनी अनिवार्यता है। अतः, आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधान सभा सदस्यों की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्ति, जो इसे अनिवार्य बनाने वाले स्पष्ट कानूनी उपबंधों के आधार पर है, संबंधित विधान सभा सदस्यों को निर्हित नहीं करेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय तारीख 16 सितम्बर, 2019 की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है।

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं, रामनाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन, मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रत्यर्थी ने,

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सदस्य होने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निर्हता उपगत नहीं की है।

31 दिसंबर, 2019

भारत के राष्ट्रपति

**राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध**

निर्वाचन सदन

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड-नई दिल्ली, 110001

2018 का निर्देश मामला सं. 11(पी)

**[दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]**

संदर्भ : 2018 का निर्देश मामला सं. 11(पी) - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश, जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह की अभिकथित निर्हता के प्रश्न के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है।

**राय**

यह भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश तारीख 15.11.2018 है जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या दिल्ली छावनी (सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 38) से दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

2. उक्त निर्देश में, भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष श्री संजीव कुमार राजपूत (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “याची” कहा गया है) द्वारा फाइल की गई याचिका तारीख 13.08.2018 से निर्हता का प्रश्न उद्भूत हुआ है जिसके द्वारा याची ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “दि.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991” कहा गया है) की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन श्री सुरेन्द्र सिंह (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “प्रत्यर्थी” कहा गया है) की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “न.दि.न.पा.प.” कहा गया है) की सदस्यता के कारण निर्हता की मांग की गई है।

3. प्रत्यर्थी, दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन में तारीख 10.02.2015 को दिल्ली छावनी (सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 38) से विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है।

4. तत्पश्चात् प्रत्यर्थी को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “लो.नि.वि.” कहा गया है) द्वारा अगस्त, 2015 में फ्लैट सं. 12, टाइप-V, यशवंत प्लेस बाजार, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली का किराया मुक्त आवास आबंटित किया गया था जो उसी समय से उसके अधिभोग में रहा है।

5. प्रत्यर्थी, जो दिल्ली छावनी से दिल्ली विधान सभा का सदस्य है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना तारीख 05.09.2014 द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, “न.दि.न.पा.प. अधिनियम, 1994” कहा गया है) की धारा 4(1)(ख) के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त अधिसूचना में यह और कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सदस्य के रूप में तब तक बना रहेगा, जब तक वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित दिल्ली विधान सभा सदस्य के रूप में बना रहता है।

6. इस समय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 4 को ध्यान में रखना संगत होगा, जो निम्नानुसार है :

**"4. परिषद् की संरचना (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-**

(क) एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारियों से होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा;

(ख) दो सदस्य दिल्ली की विधान सभा के होंगे जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली के क्षेत्र समाविष्ट हैं;

(ग) पांच सदस्य, जो केंद्रीय सरकार या सरकार या उनके उपक्रमों के अधिकारियों में से होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; और

(घ) चार सदस्यों, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, दिल्ली के मुख्य मंत्री के परामर्श से, वकीलों, डॉक्टरों, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, इंजीनियरों, कारबार और वित्तीय परामर्शदाताओं, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, श्रमिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनके अंतर्गत समाज वैज्ञानिक, कलाकार, मीडिया व्यक्ति, खेलकूद से संबंधित व्यक्ति और किसी अन्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ङ) उस निर्वाचन क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संसद् सदस्य;

**(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तेरह सदस्यों में से कम से कम,-**

(क) तीन सदस्य स्त्रियां होंगी ;

(ख) दो सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे, जिनमें से एक सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से होगा।

**(4) केंद्रीय सरकार, दिल्ली के मुख्य मंत्री के परामर्श से, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से उपाध्यक्ष को नामनिर्देशित करेगी।"**

7. याची ने यह अभिकथन किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने प्रत्यर्थी को 18000/- रुपए प्रतिमास के किराए पर एक सज्जित फ्लैट अर्थात् फ्लैट सं. 13 टाइप-V, यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली आबंटित किया। इसके अतिरिक्त, यह भी अभिकथित किया गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने प्रत्यर्थी को पालिका केंद्र भवन, नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय में सज्जित कार्यालय निःशुल्क आबंटित किया। इस संबंध में, याची ने यह कथन किया है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा आबंटित ऊपर उल्लिखित दोनों संपत्तियों में से प्रत्येक के किराए की बाजार मासिक दर लगभग 1,00,000/- रुपए है।

8. प्रत्यर्थी की निर्रहता का प्रश्न इस आधार पर उत्पन्न हुआ है कि प्रत्यर्थी ऊपर उल्लिखित संपत्तियों के कब्जे और अधिभोग से ऐसे फायदे प्राप्त कर रहा है, जो, सदस्य, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पद को धारण करने से उद्भूत होने वाला फायदा है और इसलिए, वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के अधीन लाभ के पद को धारण करने के लिए निर्रहित किए जाने का पात्र है।

9. वर्तमान मामले में विचारार्थ मुख्य मुद्दा यह है कि क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सदस्यता को, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थान्तर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन के अधीन "लाभ का पद" धारण करने

वाला समझा जा सकता है। “लाभ का पद” गठित करने के लिए मुख्य संघटक यह है कि प्रश्नगत पद सरकार के अधीन पद होना चाहिए।

10. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (उपरोक्त) की धारा 4 के मात्र पठन से पूर्णतः यह स्पष्ट हो जाता है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में ऐसे दो विधान सभा सदस्यों, जिन्हें किसी ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया है, जो पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आता है, को नियुक्त करना कानूनी अनिवार्यता है।

11. इस प्रकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति विधि के आधार पर की गई है और सरकार को, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित विधान सभा सदस्यों में से इस नियुक्ति को करने की जिम्मेदारी दी गई है।

12. यहां यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि वर्तमान निर्देश में उद्भूत मुद्दा अधिक अनिर्णीत विषय नहीं है। श्रीमति शीला दीक्षित और श्री करण सिंह तंवर की निर्हता की मांग उनकी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सदस्यता के आधार पर की गई थी और राय तारीख 05.02.2012 द्वारा, आयोग ने, यह अभिनिर्धारित किया था कि संबद्ध विधान सभा सदस्य नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन के आधार पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य बन गए थे और इस प्रकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन निर्हता लागू नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले में वैसा ही प्रश्न इन्हीं आधारों पर इन्हीं संपत्तियों के संबंध में पहले भी उत्पन्न हुआ था और राय तारीख 31.03.2017 द्वारा, आयोग ने मुद्दे पर उपरोक्त अभिमत को दोहराया था।

13. अतः, इस आयोग ने संगत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि इसको अनिवार्य बनाने वाले स्पष्ट कानूनी उपबंधों के आधार पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति, संबंधित विधान सभा सदस्यों को निर्हित नहीं करेगी।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस पद या ऐसे लाभों या फायदों की प्रकृति की और जांच करे जिनके लिए इनका धारक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की अपनी सदस्यता के आधार पर हकदार हो। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि प्रत्यर्थी किन्हीं ऐसे फायदों का लाभ ले रहा है जिनके लिए वह हकदार नहीं है तो यह समुचित प्राधिकारी के लिए एक मुद्दा है कि वह इसकी जांच करे और यह इस आयोग के अधिकार क्षेत्र और अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है।

15. अतः, आयोग की, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन यह राय है कि प्रत्यर्थी ने, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सदस्य होने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निर्हता उपगत नहीं की है।

-ह-

(अशोक लवासा)

निर्वाचन आयुक्त

-ह -

(सुनील अरोड़ा)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

-ह -

(सुशील चंद्रा)

निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 16.09.2019

[फा. सं. एच-11026/3/2019-वि. 2]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2020

**S.O. 273(E).**—The following Order made by the Hon'ble President is published for general information:-

**ORDER**

31<sup>st</sup> December, 2019

Whereas Shri Sanjeev Kumar Rajput (hereinafter, "Petitioner") has addressed a petition dated the 13<sup>th</sup> August, 2018, to the undersigned whereby he has sought disqualification of Shri Surender Singh (hereinafter, "Respondent") under article 191(1)(a) of the Constitution read with section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory Act, 1991 (hereinafter, "GNCTD Act, 1991") by reason of his membership of the New Delhi Municipal Council (hereinafter, "NDMC").

And whereas the Petitioner has brought out that the Respondent was elected as a member of the Delhi Legislative Assembly from No. 38 Delhi Cantonment Assembly Constituency on 10<sup>th</sup> February, 2015 in the general election to the Delhi Legislative Assembly, 2015. Thereafter, the respondent was allotted rent free accommodation of Flat No. 12, Type V, Yashwant Place Market, Chanakyapuri, New Delhi by the Public Works Department (PWD) of the Government of National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), in August, 2015, which has been occupied by him since then. The Respondent, being a member of the Delhi Legislative Assembly from Delhi Cantonment, was appointed as a member of NDMC as per section 4(1) (b) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 vide Notification dated 05.09.2014 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India.

And whereas the Petitioner has alleged that the NDMC has allotted a well furnished flat, i.e. Flat No. 13, Type V, Yashwant Place Market, Chanakyapuri, New Delhi at a rent of Rs. 18000 per month to the respondent. Additionally, the NDMC has also allotted a furnished office at its Head Office at Palika Kendra Bhawan, New Delhi, to the Respondent free of cost. According to the Petitioner, the market monthly rate of rent of both the abovementioned properties allotted by NDMC is around Rs. 1,00,000/- each.

And whereas the Petitioner has alleged that the Respondent is holding an office of profit on the ground that he is deriving benefits by possession and occupation of the above mentioned properties which is a benefit accruing for holding office of Member, NDMC and therefore deserves to be disqualified for holding office of profit under the Government of NCT of Delhi.

And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 on the question whether the Respondent has become subject to disqualification under Article 191(1) (a) of the Constitution of India read with section 15(1) (a) of the said Act.

And whereas the Election Commission of India, after examining the petition has opined that a bare reading of section 4 of the NDMC Act, 1994 makes it abundantly clear that it is a statutory mandate to appoint two such MLAs to NDMC who have been elected to the Delhi Legislative Assembly from a Assembly Constituency which falls wholly or partly in the NDMC area. Therefore, the Commission has held that the appointment of MLAs as member of NDMC is by virtue of express statutory provisions mandating the same shall not disqualify the concerned MLAs. A copy of the opinion dated September, 16, 2019, given by the Election Commission of India is annexed hereto.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby hold that the Respondent has not incurred disqualification under article 191(1) (a) of the Constitution of India read with section 15 (1) (a) of the Government of NCT of Delhi Act, 1991 by reason of his being a member of NDMC.

31<sup>st</sup> December, 2019

President of India

## ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

## REFERENCE CASE NO. 11 (P) OF 2018

**[Reference from the Hon'ble President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991]**

*In re: Reference Case No. 11 (P) of 2018 – A reference from the Hon'ble President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of Shri Surender Singh, Member of the Legislative Assembly of Delhi under article 191 (1)(a) of the Constitution of India read with Section 15 (1) (a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991*

## OPINION

This is a reference, dated 15.11.2018, received from the Hon'ble President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question whether Shri. Surender Singh, Member of the Legislative Assembly of Delhi from Delhi Cantonment (Assembly Constituency No. 38), has become subject to disqualification under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition, dated 13.08.2018 filed by Shri. Sanjeev Kumar Rajput (hereinafter the "**Petitioner**") before the Hon'ble President of India, whereby the Petitioner has sought disqualification of Shri. Surender Singh (hereinafter the "**Respondent**") under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter, the "**GNCTD Act of 1991**") by reason of his membership of the New Delhi Municipal Council (hereinafter, "**NDMC**").

3. The Respondent was elected as a Member of the Delhi Legislative Assembly from Delhi Cantonment (Assembly Constituency No. 38) on 10.02.2015 in the General Election to the Legislative Assembly of Delhi.

4. Thereafter, the Respondent was allotted rent free accommodation of Flat No. 12, Type V, Yashwant Place Market, Chankakya Puri, New Delhi in August 2015 by the Public Works Department (PWD) of Government of National Capital Territory of Delhi (hereinafter, "**PWD**"), which has been occupied by him since then.

5. The Respondent, being a member of Delhi Legislative Assembly from Delhi Cantonment, was appointed as a member of NDMC as per Section 4(1)(b) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (hereinafter, "**NDMC Act of 1994**") vide Notification dated 05.09.2014 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India. The said Notification further stated that the Respondent would continue to be a member of NDMC so long as he continues to be the Member of the Delhi Legislative Assembly elected from any Assembly Constituency falling in NDMC area.

6. At this juncture, it is pertinent to take note of Section 4 of the NDMC Act, 1994 which reads as under:

**"4. Composition of the Council.** (1) *The Council shall consist of the following members, namely:—*

*(a) a Chairperson, from amongst the officers, of the Central Government or the Government, of or above the rank of Joint Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi;*

*(b) two members of Legislative Assembly of Delhi representing constituencies which comprise wholly or partly the New Delhi area;*

*(c) five members from amongst the officers of the Central Government or the Government or their undertakings, to be nominated by the Central Government; and*

*(d) four members to be nominated by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi to represent from amongst lawyers, doctors, chartered accountants, engineers, business and financial consultants, intellectuals, traders, labourers, social workers including social scientists, artists, media persons, sports*

*persons and any other class of persons as may be specified by the Central Government in this behalf;*

*(e) the Member of Parliament, representing constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area.*

*(3) Out of the thirteen members referred to in sub-section (1), there shall be, at least,—*

*(a) three members who are women;*

*(b) two members belonging to the Scheduled Castes, out of which one member shall be from the members nominated under clause (d) of sub-section (1).*

*(4) The Central Government shall nominate, in consultation with the Chief Minister of Delhi, a Vice-Chairperson from amongst the members specified in clauses (b) and (d) of sub-section (1).”*

7. The Petitioner has alleged that the NDMC allotted a furnished Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi at a rent of Rs. 18,000/- per month to the Respondent. Additionally, it is also alleged that the NDMC allotted a furnished office at its Head Office at Palika Kendra Bhawan, New Delhi to the Respondent free of cost. In this regard, the Petitioner has stated that the market rate of rent of both the abovementioned properties allotted by NDMC is around Rs. 1,00,000/- each.

8. The question of disqualification of the Respondent is raised on the ground that the Respondent is deriving benefits by possession and occupation of the above mentioned properties which is a benefit accruing from the holding of the office of Member, NDMC and therefore deserves to be disqualified for holding office of profit under the Government of NCT of Delhi.

9. The primary issue for consideration in the present case is whether membership of NDMC can be considered as holding an “office of profit” under Government of NCT of Delhi, within the meaning of Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991. The primary ingredient to constitute an “office of profit” is that the office in question must be an office under the government.

10. A bare reading of Section 4 of the NDMC Act, 1994 (supra) makes it abundantly clear that it is a statutory mandate to appoint two such MLAs to NDMC who have been elected to the Delhi Legislative Assembly from an Assembly Constituency which falls wholly or partly in the NDMC area.

11. Thus the Respondent’s appointment as a member of NDMC is by virtue of law and the Government has been given the responsibility to make this appointment from among the MLAs elected from the constituencies falling under NDMC area.

12. It is also pertinent to note that the issue raised in the present reference is no longer *res integra*. Disqualification of Smt. Sheila Dixit and Shri Karan Singh Tanwar was sought on ground of their membership of NDMC and vide Opinion dated 05.02.2012, the Commission held that the concerned MLAs had become members of NDMC under Section 4 of the NDMC Act, 1994 by virtue of their election from the Assembly Constituency falling in the NDMC area and thus, did not attract disqualification under Section 15(1) (a) of the GNCTD Act, 1991. Further, a similar question was raised earlier in the case of the present Respondent as well with regard to the same properties on the same grounds and vide Opinion dated 31.03.2017, the Commission reiterated the above view on the issue.

13. Therefore, this Commission has consistently held that appointment of MLAs as Member of NDMC by virtue of express statutory provisions mandating the same shall not disqualify the concerned MLAs.

14. In view of the above, it is not necessary for the Commission to go further into the examination of the nature of this office or the profits or benefits that a holder thereof may be entitled to by virtue of his membership of NDMC. Furthermore, it is necessary to note that if the Respondent is availing any benefits to which he is not entitled, it is an issue for the appropriate authority to look into and does not fall within the domain and jurisdiction of this Commission.



15. Therefore, this Commission hereby opines under Section 15(4) of the GNCTD Act, 1991 that the Respondent has not incurred disqualification under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of NCT of Delhi Act, 1991 by reason his being a member of NDMC.

-sd-

(Ashok Lavasa)

Election Commissioner

-sd-

(Sunil Arora)

Chief Election Commissioner

-sd-

(Sushil Chandra)

Election Commissioner

**Place:** New Delhi

**Date:** 16.09.2019

[F. No. H-11026/3/2019-Leg.II]

Dr. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.